ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Achievemcnts of Anti-poverty Programmes

+

*143. PROF. AJIT KUMAR MEHTA :

SHRI RASHEED MASOOD :

Wiil the Minister of PLANNING be pleased to state :

(a) the details of the anti-poverty programmes taken up by the Government so far and the results achieved; and

(b) the impediments, if any, in the implementation of these programmes and steps taken by Government to remove them ?

THE MINISTER OF PLANNING : (SHRI P. C. SETHI) : (a) and (b) A statement is placed on the Table of the House.

Statement

The major anti-poverty programmes in operation during the Sixth Five Year Plan are ; (i) the Integrated Rural Development Programme (IRDP) ; (ii) the National Rural Employment Programme (NREP), and (iii) the Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP). Salient features of the programmes are as follows :

The Integrated Rural Development Programme aims to assist 15 million families @ 3000 families per Block through provision of income generating productive assets to be financed by a combination of Government subsidy and institutional credit.

The National Rural Employment Programme has the three-fold objective of ;

(i) Generation of additional gainful employment in the rural areas to the extent of 300 to 400 million mandays per annum ;

(ii) Creation of durable community assets in the rural areas ; and

(iii) Improvement of nutritional level of workers through increased income and payment of wages in part in the form of foodgrains.

The Rural Landless Employment Guarantee Programme was launched in 1983-84 The programme aims to provide upto 100 days employment in a year to at least one member of each rural landless household.

Details of the financial and physical achievements under these programmes are given in Annexures 1 & II.

Integrated Rural Development Programme The major impediments in the implementation of this programme are difficulties in the smooth flow of credit ; inadequate infrastructural support ; and limitations of the administrative machinery.

A High Level Committee has been set-up in the Ministry of Rural Development to review the problems of flow of credit. As a result, instructions have been issued by the Government, Reserve Bank of India ; and the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to facilitate easy flow of credit.

As regards infrastructural support, the Government of India have urged the State Governments to provide maximum support through normal sectoral programmes In addition, a provision has been made for using upto 10 per cent of the IRDP funds for programme specific infrastructural arrangements.

As for the administrative set-up, a special scheme for strengthening the Block Level machinery and for providing a Monitoring Cell at the State level is in operation under which the Central Government meets 50 per cent of the cost. In addition, a District Rural Development Agency (DRDA) has already been set-up in each District, with an appropriate staffing pattern for implementation of the IRDP and other anti-poverty programmes.

National Rural Employment Programme. Some of the major problems noticed in this programme are lack of a proper shelf of

projects and non-availablity of guide norms and technical manuals in local languages at the field level which have an adverse impact on the quality and durability of the projects.

The attention of the State Governments has been drawn to these problems. In addition, they have been allowed to use upto 5 per cent of the allocation for appropriate strengthening of the administrative infrastructure at various levels to facilitate proper planning and supervision of the projects.

Rural Landless Employment Guarantee Programme. Since this programme has been launched only recently, no major constraint has yet come to notice.

Annexure I

Statement showing Financial and Physical Progress under IRDP in Sixth Five Year Plan

Items	Unit	1980-85	1980-83	1983-84	1984-85
I. R. D. P.					
1. Financial Allocation	(Rs. crores)	1500.00	952.09	407.36	451.94
2. Utilisation	(Rs. crores)		782.88	406.09	
3. Utilisation as % of allocation	(%)		82.23%	99.7%	
4. Term Credit mobilised	(Rs. crores)	3000.00	1470.62	773.51	
5. **No. of Beneficiaries**					
(a) Envisaged Target	(In million)	15.00	9.00	3.05	3.00
(b) Actually assisted	,,		8.90	3.05	
(c) No. of Scheduled Castes (1) & Scheduled Tribes	,,		3.19	1.54	
(d) Scheduled Castes & Scheduled Tribes as percentage of total beneficiaries	(%)		35.8%	50 49%	

(1) The Programme stipulates that at least 30% of the beneficiaries should be Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

Annexure II

Statement showing Financial and Physical Progress Under NREP and RLEGP in Sixth Five Year Plan

		Sixth Plan outlay (1980-85) Rs. 1620 crores				
	Unit	1980-81	1981-1982	1982-83	1983.84	1984 85
I. N. R. E. P.						
1. Plan Outlay	(Rs. crores)	340.00	360.00	380.00	397.52	457.53
2. Utilisation	,,	217.53	317.70	394.73	390.06(1)	7.56 upto 1 May 1984 (provisional)
3. Foodgrains made available	Lakhs MTS)	15.28	3.79	3.92	4.46(2)	3.29
4. Foodgrain utitisation	,,	13.34	2.29	1.59	1.45(2)	0.35 upto May 1984 (provisional)
5. Generation of mandays of Employment	(in million mandays)	413.58	354.52	350.10 (provisional)	302.02 (provisonal) upto May, 1984)	18.90
II. R. L. E. G. P.						
1. Outlay	(Rs. crores)				100 00	400.00
2. Target of Employment	(In million mandays)				300.00	
3. No. of Projects approved	(Number)				220.00	
4. Cost of Projects approved	(Rs. crores)				616.95	

(1) It is provisional since all the States have not yet supplied information up to March 1984.

(2) The information upto March 1984 is awaited in respect of some of the States.

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, गरीबी हटाने के लिए जिन तीन कार्यक्रमों, आइ.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी. और आर.एल.इ.जी.पी. का उल्लेख किया गया है। उनको कार्यान्वित करने के लिए जिस तंत्र की स्थापना हुई है उसके शीर्ष पर जिलाधिकारी को रखा गया है। लेकिन जिलाधिकारी प्रशासनिक बोझ से इतने दबे हुए रहते हैं कि बहुधा उनको इन सब विकास कार्यों के लिए समय निकाल पाना संभव नहीं होता। इस तंत्र के शीर्ष पर जो बैठे उसमें लचीलापन, प्रवीणता और अनुभव होना आवश्यक है और इसके साथ-साथ आवश्यक है कि जिन लोगों को लाभ पहुंचता हो, निर्णय लेने के स्थान पर इनकी सक्रिय भागीदारी हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुधा इसका दुरुपयोग हो जाता है। लोग ऐसी सहायता को या तो संशय की दृष्टि से देखते हैं या उसको अनुदान समझते हैं और अनुदान समझते हैं तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता। एफ.ए.ओ. और आइ.एल.ओ. ने भी अपने अध्ययन और अनुभव से यही पाया है। ऐसी परिस्थिति में जनता पार्टी के शासन में 1978 में जो ड्राफ्ट प्लान था उसमें इसका उल्लेख किया गया था, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस विषय में उनकी क्या राय है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जब तक इस प्लान को इम्पलीमेंट करने के लिए कोई सक्षम अधिकारी नहीं रखा जाएगा, यह बात सही है कि वह प्लान ठीक तरह से इम्पलीमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन जिला अधिकारी से बेहतर अधिकारी कोई जिले में हो नहीं सकता है। उनको असिस्ट करने के लिए उनके अधीन बहुत सारे अधिकारी होते हैं। उनका भी उपयोग किया जाता है। इसलिए यह ठीक से काम कर रहा है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स को हिदायत दी गई है कि वे इस सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को सूचना दें कि वह इस काम को ठीक से इम्पलीमेंट करें।

जनता पार्टी के समय में जहां तक प्लान का सवाल है उस समय तो कोई प्लान था नहीं और प्लान के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं थी।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने ड्राफ्ट प्लान का उद्धरण दिया था। प्लान था या नहीं था, यह मैंने नहीं पूछा था। मैंने पहले ही कहा था कि जरूर जिला अधिकारी इसके लिए सुयोग्य कर्मचारी है, परन्तु मैंने यह सवाल उठाया था कि प्रशासनिक बोझ से वह इतने दबे हुए होते हैं कि विकास कार्यों के लिए बहुधा समय नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए वह अपने कर्त्तव्य का निर्वाह अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। यह मैंने कहा था।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि ग्रामीण मजदूरों के संगठन पर आइ०एल०ओ० के 141वें कन्वेंशन में तय पाया गया था जिसे 1978 में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि ग्रामीण विकास बिना प्रभावशाली ग्रामीण सह-श्रमिक-संगठन के संभव नहीं हो सकता। इन संगठनों को आर्गेनाइज़ करने के लिए अवैतनिक आर्गेनाइज़र की भी नियुक्ति हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि कितने राज्यों के लिए कितनी-कितनी बहाली हुई थी और उसका क्या परिणाम निकला। अगर अपेक्षित परिणाम नहीं निकला क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों के कोई प्रभावशाली संगठन कहीं भी नहीं हैं तो सरकार ने इसके बारे में क्या सोचा और प्रभावशाली संगठन के निर्माण के विषय में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : गैर-सरकारी संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया जाता है। ये

आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं कि ऐसे लोगों की बहाली किस-किस जगह हुई है और किस-किस जगह नहीं हुई है। लेकिन मैं आंकड़े इकट्ठा करके माननीय सदस्य को पहुंचा दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने रूरल लेंडलैस गारन्टी प्रोग्राम में रखा है कि 50 प्रतिशत उसका मैटीरियल कम्पोनेन्ट होगा और 50 प्रतिशत लेबर के लिये देंगे और सिर्फ 5 परसेंट आपने सुपरविजन चार्जेज रखा है। पिछले कामों से यह अनुभव किया गया है कि मैटीरियल सीमेंट, चूना, पत्थर और अन्य वस्तुओं से 50 परसेंट से काम नहीं चलता। 75 परसेंट जब तक नहीं बनायेंगे या 65 परसेंट और 35 परसट का रेशियो नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। इस तरह से काम अधूरे रह जाते हैं। क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि हम परिवारों को काम देना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं उन 100 परिवारों को तब ही आप काम दे सकते हैं जब कि आप 50 परसेंट ज्यादा कम्पोनेन्ट देंगे। यह 50 परसेंट में आता नहीं है और इससे एसैट नहीं बनता, देश में पूंजी नहीं बनती। क्या आप इस पर विचार करेंगे और इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : इस समय तो प्लान में 50 परसेंट ही उसके लिये रखा गया है, यदि धन और उपलब्ध हुआ तो इस 50 प्रतिशत को बढ़ाने के लिये विचार किया जा सकता है।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Sir, I would like to know from Hon. Minister whether the Government or the Planning Commission has finalised the estimates of the number of people who have been brought above the poverty line due to these anti-poverty programmes. The Government has recognised that there has been a controversy about the number of people who are being brought above the poverty line. In view of this controversy, whether the Government has now finalised the estimates of the number of people brought above the poverty line?

SHRI P.C. SETHI : The total number of people covered under the Sixth Plan period is 120 milion people. As far as the controversy concerned there was a figure mentioned by my predecessor of 57 milions while the Prime Minister has mentioned 120 milions. 120 million is also a correct figure in the manner explained earlier in the House.

श्री शिव प्रसाद साहू : मैं योजना मंत्री जी का ध्यान खासतौर से बिहार के छोटा नागपुर की तरफ दिलाना चाहूंगा। बहुत सारे काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं, विशेषकर 2-3 कामों के बारे में जानना चाहूंगा कि क्या वहां के बैंक गरीबों और पहाड़ों में बसने वालों को सही ढंग से ऋण दे रहे हैं या नहीं ?

इसके अलावा बहुत सारे गरीब और आदिवासी झगड़े में फंसते हैं, इस तरह की गड़बड़ देखने को मिल रही है कि उनसे 1500 रुपये बैल के लिये मिले, की सही करा लेते हैं और 800-900 रुपये का बैल खरीदकर उनको दिया जाता है। क्या मंत्री जी एक जांच कमेटी पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में ऐसी बनाना चाहते हैं जो यह देख सके कि हमारे प्रधान मंत्री और योजना मंत्री जो गरीबों को गरीबी-रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, और उनको जो लाभ पहुंचाना चाहते हैं वह उनको सही ढंग से मिल रहा है या नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : बैंकों ने पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस प्रकार की शाखाएं खोली हैं और उन्होंने पहाड़ी लोगों की मदद के लिये उन्हें पैसा दिया है। जहां तक कमेटी बनाने का सवाल है, ऐसी कोई कमेटी नहीं है, लेकिन इसके बनाने पर विचार किया जा सकता है।

(Interruptions)

MR. SPEAKER : I do not want the supplementary questions to increase.

Rise in Steel Price

+

*145 SHRI BALKRISHAN WASNIK :

SHRI GHUFRNA AZAM :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Government have assessed the total impact of the 15 per cent hike in steel prices including its particular impact over the wholesale price index;

(b) whether this increase could have been avoided if Government had kept a constant monitoring system towards reduction of higher administrative charges, costs and pilferage of steel plants; and

(c) if so, the facts thereof and steps being taken as an alternative to this raising prices for breaking the vicious circle prevailing over the steel trade ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI N.K P. SALVE)

(a) to (c) : A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The total impact of the 15% average increase in the price of iron and steel is expected to be marginal.

(b) and (c) The increase in the price of iron and steel had become quite unavoidable on account of increase in costs of raw materials (including coal), consumables, salaries and wages, stores and spares and average rail freight that were beyond the control of the producers, as well as the need to have a fund for assisting the export of engineering products This increase in the price of iron and steel will compensate the increase in the costs of production only partially. The integrated producers are making every effort to exercise the strictest possible control on the cost of production as well as strict security to prevent pilferage (security in the SAIL plants is enforced by the Central Industrial Security Force).

SHRI BALKRISHNA WASNIK : Sir, it has been stated that the increase in the price of iron and steel had become quite unavoidable on account of increase in costs of raw materials, consumables, salaries and wages, etc. May I know that there is a private sector also in the ordinary industry ?

May I know whether the cost of production in the private sector compares favourably with that of the public, sector, and if not, what steps Government are taking so that the productivity and efficiency is improved in the public sector also ?

SHRI N.K.P. SALVE : In the private sector the only integrated steel plant is that of Tatas as against the five integrated steel plants in the public sector. The cost per tonne of steel produced by Tatas cannot compare favourably with the steel produced by the public sector steel plants, *Inter Alia*, because the overall cost today of written down value of Tatas is Rs. 500 crores for 1.87 million tonnes of steel that are produced. Secondly, as regards the basic ingredients, iron ore and coal, the Tatas have a captive coal mine and from the coal they are able to draw upon coking coal which is of a very low ash content—it is of high quality and, therefore, the hot metal in terms of productivity that they get is much higher than ours.

As to the other aspects of the matter which the Hon. Member has raised, whether it is due to pilferage, our inability to control the cost of production and other factors that we are incurring losses, that is not so. The cost of production is going up in the private sector also as it is in the public sector. Even the private sector would have sustained the loss this year if this increase had not been given in the price of steel, the minimal increase that has been given with the barest impact on the wholesale price index.

SHRI BALKRISHNA WASNIK : The increase in price of steel is mainly due to